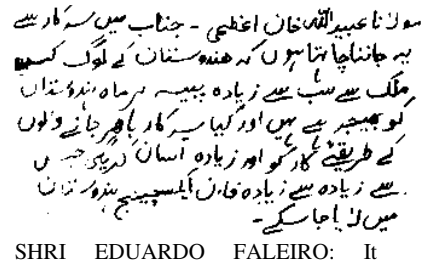

SHRI EDUARDO FALEIRO: It concerns the Ministry of Finance. All the questions regarding foreign exchange and the remittances of foreign exchange concern the Minsitry of Finance and are monitored by the Reserve Bank of India.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में नई रेलवे लाइनों और पन-विद्युत परियोजनाओं का प्रावधान किया जाना

*426. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार में नई रेल लाइनें बिछाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान छोटा नागपुर के विकास के लिए कम से कम 10,000 मेगावाट ताप विद्युत और 1,000 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन किया जाये ताकि शेष बिहार और देश के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बिहार में कोडरमा से मानिकपुर तक एक नई लाइन जिसका विस्तार जदुनाथपुर तक किया जाएगा, विचाराधीन परियोजनाओं में से एक है।

विद्युत क्षेत्र के लिए योजना कार्यक्रम प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध वास्तविक संसाधनों तथा उस क्षेत्र में प्रत्याशित ऊर्जा और विद्युत शक्ति की मांग को ध्यान में रख कर बनाया जाता है।

मध्य प्रदेश में जल-विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि

*427. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के वर्ष के दौरान योजना आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को इसकी विभिन्न प्रस्तावित और निर्माणाधीन लघु/सूक्ष्म जल-विद्युत परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई थी;

(ख) क्या उपलब्ध करायी गई धनराशि पर्याप्त थी; और

(ग) यदि नहीं, तो पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण थे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) योजना आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 1991-92 वर्ष के दौरान विभिन्न प्रस्तावित और चालू लघु/सूक्ष्म जल परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए 982 लाख रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया था। इस के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपयों में)
	लघु जल परियोजना	
	तवा एल०बी०सी० एचईपी (2×6 मेगावाट)	300
	छोटी/सूक्ष्म जल परियोजनाएं	
1.	रूद्री कनाल मिनी हाइडल (2 × 100 किलोवाट)	
2.	बरना मिनी हाइडल (2×750 किलोवाट)	
3.	चम्बल आरबीसी मिनी हाइडल (3×600 किलोवाट)	682
4.	मोरण्ड मिनी एच०एस० (3×335 किलोवाट)	(कुल राशि प्रावधान)
5.	कोरबा पश्चिम किनारा मिनी (1×800 किलोवाट)	
6.	भीमगढ़ एच०एस० (2×1200 किलोवाट)	
7.	सतपुरा रिटर्न कैनाल (2×500 किलोवाट)	

†Transliteraion in Arabic Script].

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपयों में)
8.	तिलवाड़ा मिनी हाइडल (1×250 किलोवाट)	
9.	चारगांव—जटलापुर छोटी (1×800 किलोवाट)	
10.	बहादुरपुर खरार छोटी (1×250 किलोवाट)	
11.	स्थाई छोटी एच०एस० (1×150 किलोवाट)	
12.	अकालतारा शाखा नहर (1×700 किलोवाट)	
13.	पाटन शाखा नहर (2×500 किलोवाट)	

(ख) अनुमोदित परिव्यय राज्य द्वारा प्रस्तावित परिव्यय के समान है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Responsibility of Heads of Indian Diplomatic Missions for Development of Economic and Commercial Work

*428. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to make our Heads of diplomatic missions abroad personally responsible for development of economic and commercial work; and

(b) if so, what steps are proposed to be taken to achieve that goal?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) and (b) The Government have decided that maximum emphasis should be placed by our Missions abroad in the task of promoting our economic and commercial interests. A system of quarterly reporting has been introduced to evaluate the performance of our Missions and Posts in target countries. In keeping with the new priorities, facilities available to certain select Missions and Posts have been upgraded and additional staff have provided where required. An orientation programme is being conducted for 22 selected Heads of Missions and Posts to equip them further for commercial and economic work.

Assistance by Central Government to Yarn Producing Units in Uttar Pradesh

*429. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of Textiles be pleased to state:

(a) what arc the details of assistance provided by Central Government to the yarn producing units in Uttar Pradesh since 1991 till date; and

(b) the details of demands received by the Central Government from the handloom weavers in the State and fulfilled besides supply of yarns during the above period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Government of India provides loan assistance to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) for setting up of new Weavers Cooperative Spinning Mills and expansions of existing Cooperative Spinning Mills. Government under this scheme has assisted nine Weavers Cooperative Spinning Mills in U.P. till the Seventh Plan Period. Against the total sactioned amount of Rs. 1857.025 lakhs for these mills in the State, a sum of Rs. 1843.615 lakhs was released till the end of the Seventh Plan period. The balance spill over of Rs. 13.410 lakhs in respect of four spinning mills in the State was released to National Cooperative Development Corporation during March, 1991. Under Textile Modernisation Fund Scheme, upto 31st December, 1991, Rs. 21.49 crores have been disbursed to five spinning units of Uttar Pradesh.

(b) No further proposals have been received from Government of Uttar Pradesh for either setting up of new spinning mills or for expansion of existing one in the weavers cooperative sector. The following are the details of quantity of yarn supplied to handloom weavers